Ceiling on Election Expenses

411. SHRI S. K. T. RAMACHANDRAN: Will the Minister of LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether Government are aware that the ceiling on election expenses of the candidates for Parliament and Assembly Elections are not strictly being followed ; and

(b) if so, what steps are being contemplated in this regard ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI H. R. BHARDWAJ) : (a) and (b) The Government is aware that the present ceiling fixed in 1984 has become unrealistic in the context of increasing cost all-round. In this regard, a proposal to empower the Election Commission to fix ceilling of election expenses before each general election is under the consideration of the Government.

Cost Audit of Units Manufacturing Sulphuric Acid

412. SHRI SANTOSH KUMAR SAHU:
SHRI RAJNI RANJAN SAHU :
SHRIMATI SATYA BAHIN :

Will the Minister of LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether it is a fact that several units engaged in the production of Sulphuric Acid and bulk drugs have not been subjected to Cost Audit for the past several years :

(b) if so, the names of those units and the reasons for which no audit was done ; and

(c) what steps have been taken to fix the responsibility for this lapse and to ensure that such instances do not recur ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI H. R. BHARDWAJ) : (a) and (b) The process of up-dating the lists in respect of various industries covered under cost audit is a continuous one. The list of units of various industries covered under cost audit is reviewed from time to time. This review is undertaken in consultation with the administrative Ministry concerned. Representations received from various sources are also aken into consideration while up-dating the list of companies covered under cost audit. Recently 16 more companies manufacturing sulphuric Acid and 38 more companies manufacuring Bulk Drugs have been included in the list of companies subjected to Cost Audit.

(c) Does not arise.

उत्तर प्रदेश में लोक-अदालतें

413. **श्री सत्य प्रकाश मालवीय** : क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विधिक सेवा अधिनियम, 1987 के प्रख्यापन के पश्चात् उत्तर प्रदेश में 31 मार्च, 1992 तक कितनी लोक अदालतें लगाई गई और उनका ब्यौरा क्या है ;

(ख) इन लोक अदालतों द्वारा कितने मामले निपटाए गए और उनका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या उत्तर प्रदेश में इन अदालतों की संख्या में वृद्धि किए जाने का विचार है, और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हंसराज भारद्वाज) : (क) से (ग) लोक अदालतों नियमित रूप से गठित न्यायालय नहीं है बल्कि समझा-बुझाकर और सुलह कराकर विवादों के निपटारे के लिए स्वैच्छिक प्रयास हैं । ये देश के विभिन्न भागों में, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के प्रवर्तित होने तक, समय-समय पर राज्य विधिक सहायता और सलाह बोर्डों तथा जिला विधिक सहायता समितियों द्वारा आयोजित की जा रही हैं ।

उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सहायता और सलाह बोर्ड द्वारा उपलब्ध की गई जानकारी

के अनुसार 1981-82 से और तारीख 31 मार्च, 1992 तक, उत्तर प्रदेश राज्य में 1318 लोक अदालतें आयोजित की गई हैं जिनमें 13,29,633 मामले निपटाए गए, इनमें मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के 11,734 मामले, छोटे-मोटे (जुर्माने से दंडनीय) 6,84,090 दांडिक मामले, विवाह-विषयक 5,202 मामले, 21,625 सिविल मामले, विभिन्न श्रम विधियों के अधीन 11,237 मामले, 4,79,744 राजस्व के मामले और 1,16,001 अन्य मामले हैं।

इलाहाबाद और पटना उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के रिक्त पद

414. **श्री सत्य प्रकाश मालवीय :** क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इलाहाबाद और पटना उच्च न्यायालय में इस समय न्यायाधीशों के कितने-कितने पद रिक्त हैं,

(ख) दोनों उच्च न्यायालयों में इस समय कितने-कितने न्यायाधीश हैं, और

(ग) इन पदों के कब तक भरे जाने की संभावना है और ये पद कौन-कौन सी तारीखों से रिक्त हुए हैं ?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हंस राज भारद्वाज) : (क) से (ग) तारीख 1-7-92 को इलाहाबाद और पटना उच्च न्यायालय की बाबत स्थिति निम्नलिखित थी :-

उच्च न्यायालय	स्वीकृत पदों की संख्या	कार्य कर रहे न्यायाधीश	रिक्त पदों की संख्या और वह तारीख जिस से रिक्त है
इलाहाबाद	70	69	1 (1-5-92)
पटना	35	31	1 (1-1-92 3-1-92 3-1-92 5-6-92)

इन उच्च न्यायालयों में विद्यमान रिक्त पदों को भरने के लिए संबंधित सांविधानिक प्राधिकारियों के साथ परामर्श की प्रक्रिया चल रही है। यह बताना संभव नहीं है कि ये रिक्त पद कब तक भर दिए जाएंगे।

Violation of Cost Audit Provision

415. **SHRI H. HANUMANTHAPPA :**
SHRI RAJNI RANJAN SAHU :
SHRIMATI SATYA BAHIN :

Will the Minister of LAW JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state :

(a) what are the details of cases pendin with the Registrars concerning violatio of Cost Audit Provisions ;

(b) the time since when each case pending :

(c) whether it is a fact that a meetir of Registrars was arranged and certa decisions were taken ; and

(d) if so, what are the details of suc decisions and what has been the follo up action taken after the meeting ?

THE MINISTER OF STATE IN TH MINISTRY OF LAW, JUSTICE AN COMPANY AFFAIRS (SHRI H. BHARDWAJ) : (a) and (b) The informatio